

**श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) :** महोदय, मैं एक अति लोक महत्व के विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब यूपीए की सरकार थी तो बुंदेलखण्ड पैकेज की बात हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा, गरीब और पेयजल संकट से जूझता क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र भी उसी में आता है। उसमें तीन जिले दमोह, सागर और छतरपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। एक बड़ा पैकेज बुंदेलखण्ड के लिए दिया गया था, जिसमें पेयजल की योजनाओं का बड़ा हिस्सा इसी सदन में और सदन के बाहर पीटा गया था। मैं अपनी क्षेत्र में 26 स्थानों पर गया, जहां नल-जल योजना संचालित था। एक भी योजना छः दिन से ज्यादा नहीं चली। उसकी तकनीकी खामियां और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह पूरा पैसा भारत सरकार का पैसा है और बुंदेलखण्ड पैकेज के नाम पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें की गयी थीं, लेकिन वह सारी की सारी योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में समा गयी। एक योजना की कीमत कम से कम 52 लाख रुपये से लेकर 82 लाख रुपये तक है। यह मैं उन 26 योजना की बात कर रहा हूँ, जिनको मैं देख कर आया हूँ।

**15.00 hrs.**

वहां पर सभी योजनाएं विफल हैं।

महोदय, भारत सरकार की जल संसाधन मंत्री उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री उस बात को कहें कि चाहे जो भी बुंदेलखण्ड का पैकेज बने, चाहे वह सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए हो, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए।

महोदय, मैं इस अवसर पर इतना ही मांग करता हूँ।